

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

No. 78]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/ PHALGUNA 26, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

सं. 11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर.—भारत सरकार एतद्वारा मालभाड़ा राजसहायता स्कीम, 2013 नामक भारत सरकार की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर दिनांक 22 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. भारत सरकार की अधिसूचना सं. 11 (5)/2009-डीबीए-II/एनईआर दिनांक 22 जनवरी, 2013 के मौजूदा खण्ड 10(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/संघीय प्रदेश प्रशासन की भूमिका तथा कार्य-
- (2) योजना के तहत राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र में प्राप्त सभी राजसहायता दावों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करेंगे, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव (संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग विभाग, संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के उद्योग निदेशक तथा संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित क्षेत्र के वित्त विभाग, संबंधित राज्य/संघीय प्रदेश के उत्पाद शुल्क तथा कराधान विभाग (उत्पाद आयुक्त), संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के परिवहन विभाग, संबंधित नोडल एजेंसी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2016

**No. 11(5)/2009-DBA-II/NER.**—The Government of India hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 11(5)/2009-DBA-II/NER dated the 22nd January, 2013 called the Freight Subsidy Scheme, 2013.

2. In place of existing clause 10(2) of Government of India Notification No. 11(5)/2009-DBA-II/NER dated the 22nd January, 2013, the following shall be substituted:

**10. Role and functions of the State Government/Union Territory Administration under the scheme—**

- (2) The State Govt./Union Territory Administration concerned shall set up a State Level Committee (SLC), consisting of the Principal Secretary/Secretary (Industry Department of the State Govt./Union Territory concerned), Director of Industries of the State/ Union Territory concerned and a representative each from the Finance Department of the State/Union Territory concerned, Excise and Taxation Department of the State/Union Territory concerned (Excise Commissioner), Transport Department of the State/ Union Territory concerned, nodal agency concerned and Department of Industrial Policy & Promotion, GOI to consider and recommend all subsidy claims, under the scheme, arising in the State/Union Territory.

RAVNEET KAUR, Jt. Secy.